



भारत का राजपत्र The Gazette of India

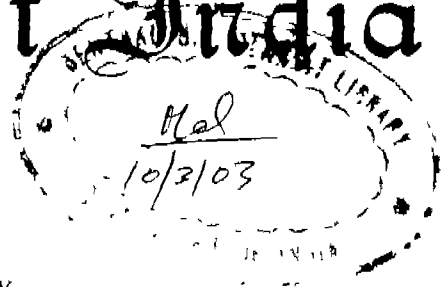
असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 226]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अगस्त 29, 2002/भाद्र 7, 1924

No. 226]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 29, 2002/BHADRA 7, 1924

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2002

विषय : रूस, यूक्रेन और कोरिया जनवादी गणराज्य से इंडक्शन हार्डनड फोर्ज्ड स्टील रोल्ल्स के भारत में आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करना।

सं. 14/3/2002.— मै. गोंन्टरमन्न पाइपर (इंडिया) लि. पश्चिम बंगाल ने 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली और क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष घरेलू उद्योग की ओर से एक याचिका दायर की है जिसमें रूस, यूक्रेन और कोरिया जनवादी गणराज्य (जिन्हे इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) से आयातित इंडक्शन हार्डनड फोर्ज्ड स्टील रोल्ल्स के पाटन का आरोप लगाते हुए अनुरोध किया गया है कि पाटनरोधी जांच की जाए और पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए। मैसर्स हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, रांची द्वारा याचिका का समर्थन किया गया है।

1. **सम्मिलित उत्पाद** इस मामले में शामिल उत्पाद इंडक्शन हार्डनड फोर्ज्ड स्टील रोल्ल्स जो फोर्ज्ड सी आर एम को (कोल्ड रोलिंग मिल्स रोल्ल्स) (300 मि.मि. से अधिक आकार के) नाम से भी जाना जाता है (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है) इन्हें मुख्यतया हॉट रोलिंग मिल्स से प्राप्त लौह एवं अलौह कॉइल्स की कोल्ड रोलिंग के लिए इस्पात संयंत्रों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है।

फोर्ज्ड रोल्ल्स सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 84 के अंतर्गत वर्गीकृत है। इसे भारतीय व्यापार वर्गीकरण (समान वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली पर आधारित) के अनुसार भी शीर्ष 8455.30.00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा वर्तमान जांच के कार्य क्षेत्र पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।

2. घरेलू उद्योग की स्थिति

यह याचिका मै. गोंटरमन्न पाइपर (इंडिया) लि. पश्चिम बंगाल द्वारा दायर की गई है और मै0हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, रांची ने इसका समर्थन भी किया है। यह बताया गया है कि छोटे उत्पादक इतने बड़े व्यास के रोल नहीं बनाते और मै. टाटा योदोगावा लि. (टागों) जमशेदपुर भी उत्पादन नहीं बल्कि केवल मशीनिंग कार्य करता है।

दिनांक 1.4.2001 से 30.6.2002 की अवधि में भारत में उत्पादित संबद्ध वस्तु के कुल उत्पादन में याचिकाकर्ता का हिस्सा 50% से अधिक रहा है और इस प्रकार नियम 5(3)(क) तथा (ख) के अनुसार घरेलू उद्योग याचिका दायर करने की स्थिति में है तथा पाटन रोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व भी करता है।

3. शामिल देश: वर्तमान जांच में शामिल देश रूस, यूक्रेन और कोरिया जनवादी गणराज्य है।

4. समान वस्तु: याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों द्वारा उत्पादित, वहां के मूल की या निर्यातित वस्तु के समान है क्योंकि दोनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। नियम 2(घ) के अर्थान्तरगत याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के समान समझा जा रहा है।

5. सामान्य मूल्य: प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि याचिकाकर्ता ने परिकलित सामान्य मूल्य जिसमें समुचित समायोजन शामिल हैं, के आधार पर संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु की सामान्य लागत का दावा किया है। याचिकाकर्ता ने इस आशय के सबूत पेश किए हैं कि पिछले तीन वर्षों में अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों ने रूस और यूक्रेन को गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना है। याचिकाकर्ता ने इस संशोधित पाटन रोधी नियमावली की दृष्टि से इस जांच के लिए यह दावा किया है कि रूस और यूक्रेन गैर बाजार अर्थव्यवस्था देश हैं। प्राधिकारी ने संशोधित पाटन रोधी नियमावली के अनुसार समुचित समायोजन करके इन देशों में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के आधार पर परिकलित लागत को प्रथम दृष्टया संबद्ध वस्तु की सामान्य कीमत माना है।

6. निर्यात मूल्य: याचिकाकर्ता को गौण स्रोत अर्थात् इन्फो झाइव इंडिया प्रा.लि. की निर्यात कीमतों पर विचार किया है जो आयात आंकड़ों और भारत में संबद्ध वस्तु के एक ग्राहक को रूस और यूक्रेन द्वारा दिए गए निर्यात आदेशों का भी संकलन करता है। याचिकाकर्ता ने बताया है कि वाणिज्य आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) द्वारा प्रकाशित आंकड़े इस तथ्य की दृष्टि से संगत नहीं हो सकते कि विभिन्न भार वाले विभिन्न रोलों को सीमाशुल्क के एक शीर्ष के अंतर्गत इकट्ठा किया जा सकता है, अतः उनसे वह कीमत मालूम नहीं होगी जिस पर इन वस्तुओं का भारत में आयात किया गया है। कारखाना द्वार पर निर्यात मूल्य का आंकलन उत्तराई प्रभार, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा और पत्तन हैंडलिंग प्रभारों का समायोजन करके किया गया है।

7. पाटन मार्जिन: इस बात के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं कि जिस कीमत पर संबद्ध वस्तु भारत को निर्यात की गई है, की तुलना में संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु की सामान्य कीमत काफी अधिक है

जिससे प्रथम दृष्टि में ऐसा मालूम होता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है। संबद्ध देशों अर्थात् रूस, यूक्रेन और कोरिया जनवादी गणराज्य का पाटन मार्जिन क्रमशः 32.96%, 69.79%, 11.06% परिगणित होता है।

8. **क्षति और कारणात्मक संबंध:** प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तु इस तरह बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा है जिससे उसे अपनी उचित उत्पादन लागत प्राप्त नहीं हुई, परिणामतः उसे वित्तीय घाटा हुआ। प्राधिकारी ने यह नोट किया कि मै. हैपी इंजिनियरिंग कॉर्पोरेशन, रांची ने बताया कि उन्हें संबद्ध देश द्वारा तथाकथित पाटन के कारण लाभप्रदता में घाटा हुआ और विक्रय आर्डर भी कम मिले हैं। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया कि संबद्ध वस्तु की मांग को कोई बाधक घटक न मानते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति का तथाकथित पाटन के साथ प्रथम दृष्टया कोई कारणात्मक संबंध है।

9. **पाटन रोधी जांच की शुरुआत:** उपर्युक्त पैराग्राफों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की विद्यमानता, मात्रा और उसके प्रभाव की जांच शुरू करते हैं।

10. **जांच की अवधि:** वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल 2001 से 30 जून, 2002 तक है।

11. **सूचनाएं प्रस्तुत करना:** उक्त संबद्ध देशों के संबंधित ज्ञात निर्यातकों और भारत में आयातकों को निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित तरीके से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने के लिए और निम्नलिखित को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग-अलग पत्र लिखे जा रहे हैं-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी निम्न प्रकार से नियत समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और निर्धारित तरीके से जांच से संबंधित अपने निवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

12. **समय सीमा:** वर्तमान जांच संबंधी कोई जानकारी लिखित रूप में इस प्रकार भेजी जानी चाहिए कि वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर प्राधिकारी को उपर्युक्त पते पर पहुंच जाए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से पत्र लिखे जा रहे हैं उनके लिए उनको लिखे पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना प्रस्तुत करना आवश्यक है।

13. सभी पक्षकारों को पाटनरोधी नियम 7(2) के अनुसार दी गई किसी भी सूचना का अगोपनीय सारांश अवश्य प्रस्तुत करना होगा। तथापि, यह सूचना नियम 7(1) और 7(2) के अनुसार की जाने वाली स्वीकृति के अधीन होगी।

14. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण: नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं।

15. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने से मना करता है या उचित समयावधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में पर्याप्त बाधा डालता है तो प्राधिकारी, अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

एल. बी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2002

Subject : Initiation of Anti-Dumping investigation concerning imports of Induction Hardened Forged Steel Rolls from Russia, Ukraine and Korea RP.

No. 14/3/2002.— M/s Gontermann-Piper(India) Ltd., West Bengal on behalf of the Domestic industry has filed a petition, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) alleging dumping of Induction Hardened Forged Steel Rolls from Russia, Ukraine and Korea RP (herein after called subject countries) and has requested for Anti-Dumping investigation and levy of Anti-Dumping Duties. The petition is also supported by M/s Heavy Engineering Corporation, Ranchi

1. **Product involved:** The product involved in the present petition is Induction Hardened Forged Steel Rolls, also known as Forged CRM(Cold Rolling Mills Rolls) (above 300 mm size) (hereinafter referred to as subject goods). These are primarily used by steel plants for cold rolling of ferrous and non-ferrous coils obtained from Hot Rolling Mills.

Forged Rolls is classified under Chapter 84 of the Custom Tariff Act, 1975. It is further classified as per Indian Trade Classification (Based on Harmonized Commodity Description and Coding System) under the heading 8455.30.00. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

2. Domestic Industry standing:

The petition has been filed by M/s Gontermann-Piper (India) Ltd., West Bengal and is also supported by M/s Heavy Engineering Corporation, Ranchi. It has been indicated that small scale producers do not produce such large dia Rolls and also M/s Tata Yodogawa Ltd. (TAYO), Jamshedpur only does the machining work and not production.

The petitioner in the period 1.4.2001 to 30.6.2002 constitutes more than 50% of the total production of subject goods in India and thus have the standing to file the petition on behalf of the domestic industry as per rule 5(3) (a) and (b) and also represents the Domestic Industry as per Rule 2(b) of Anti-Dumping Rules.

3. Countries involved: The countries involved in the present investigation are Russia, Ukraine and Korea RP.**4. Like articles:** The petitioner has claimed that the goods produced by them are like article to the goods produced, originating in or exported from the subject countries as both are used interchangeably. The goods produced by the petitioner are being treated as like articles to the goods imported from the subject countries within the meaning of the Rules 2(d).**5. Normal value:** The Authority notes that the petitioner has claimed normal value of subject goods in the subject countries on the basis of the constructed normal value with appropriate adjustments. The petitioners have submitted evidence to the effect that Russia and Ukraine have been treated as non-market economy by other investigating authorities in the preceding three years. The petitioner in view of this amended Anti Dumping Rules have claimed Russia and Ukraine as the non-market economy for the purpose of this investigation. The Authority has prima facie considered the normal value of the subject goods in the subject countries as constructed on the basis of cost of production of subject goods for these countries with appropriate adjustments as per the amended Anti Dumping Rules.**6. Export Price:** The petitioners have considered the export prices of the secondary source viz. Info Drive India Pvt. Ltd. which compiles customs imports data and also the export orders placed from Russia and Ukraine to one of the customers of the subject goods in India. The petitioner has indicated that the data published by Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCI&S) may not be relevant in view of the fact that different rolls with different varying weights may be clubbed under one custom head thus not being indicative of the price at which these goods have been imported into India. The ex-factory export price has

been evaluated by allowing adjustments on landing charges, ocean freight, marine insurance, inland freight and port and handling charges.

7. **Dumping margin:** There is sufficient prima-facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the price at which it has been exported to India indicating prima-facie that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject countries. The prima facie dumping margin from these subject countries viz. Russia, Ukraine and Korea RP Comes to 32.96%, 69.79% and 11.06% respectively.
8. **Injury and Causal Link :** The Authority notes that the Domestic Industry has been forced to sell the subject goods which have not permitted them recovery of reasonable cost of production leading to financial losses. The Authority notes that M/s Heavy Engineering Corporation, Ranchi have indicated loss on profitability and lost sales orders on account of alleged dumping from the subject countries. The Authority also notes that in view of demand of subject goods not a constraining factor, the injury caused to the Domestic Industry prima facie has a causal link with the alleged dumping.
9. **Initiation of Anti-Dumping investigation:** The authority in view of the foregoing paragraphs initiates anti-dumping investigation into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.
10. **Period of investigation:** The period of investigation for the purpose of present investigation is 1st April, 2001 to 30th June, 2002.
11. **Submission of Information:** The exporters in the said subject countries and the importers in India known to be concerned are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and make their views known to:-

The Designated Authority
Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Udyog Bhavan
New Delhi-110011.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

12. **Time limit:** Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than 40 days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers who are being addressed separately are however, required to submit the information within 40 days from the date of letter addressed to them separately.
13. All parties must provide a non-confidential summary of any information provided on a confidential basis in terms of Anti-Dumping Rule 7(2). However, such information will be subject to acceptance in terms of Anti-Dumping Rule 7(1) and 7(2).
14. **INSPECTION OF PUBLIC FILE:**

In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.
15. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

